राज्य	करोड़ रु० में
ख. गैर-विशेष श्रेणी राज्य	
आंध्र प्रदेश	534.36
बिहार	772.31
गोवा	42.00
गुजरात	229.23
हरियाणा	113.11
कर्नाटक	265.25
केरल	296.00
मध्य प्रदेश	493.30
महाराष्ट्र	375.31
उड़ीसा	340.55
पंजाब	164.57
राजस्थान	385.81
तमिलनाडु	460.17
उत्तर प्रदेश	1081.57
प. बंगाल	379.35
जोड़ : ख	5932.89
सकल जोड़ (क+ख)	8837.88

Census of Industrial Establishments in terms of hired labour

3576. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether the census of establishments in non-agricultural sector has recently been completed; and

(b) if so, what is the number of establishments without any hired labourer, establishments with 1 to 5 hired labourers and establishments with 6 to 9 labourers?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI SUKH RAM): (a) A census of all enterprises in agricultural (except crop production and Plantation) and non-agricultural sectors was carried out in 1990 throughout the country except Jammu and Kashmir.

(b) As per the quick estimates, there were about 25 million enterprises in the country excluding Jammu and Kashmir in 1990. Out of these 25 million enterprises, 17.9 million enterprises were run without any hired labour on a regular basis. The breakdown of the remaining 7.1 million enterprises by size class of labour, whether hired or not, is not available.

सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा परियोजनाओं को मंजूरी

3577. **श्री विनोद शर्मा :** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 मई, 1992 के "इकोनोमिक टाइम्स" में 'पी आई बी क्लीअरस प्रोजेक्ट्स वर्थ रोज 14295 करोड़" शीर्षक के छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा 15 परियोजनाओं के निर्माण के लिए जो राशि आवंटित की गई है वह बहुत मामूली है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी आशंका है कि उपर्युक्त परियोजनायें अपने निर्धारित समय के भीतर पूरी नहीं हो पायेंगी ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार ने ऐसी आशंकाओं के संबंध में विभागों को अवगत करा दिया है ; ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री और गर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सुख राम) : (क) जी, हां । तथापि सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) अप्रैल, 1992 में विद्युत, पैट्रोलियम तथा इस्पात क्षेत्रक में तीन परियोजनाओं के लिए 9215.19 करोड़ रूपए (दोनों नए एवं संशोधित) कुल निवेश की स्वीकृति दी है और न कि 11 परियोजनाओं के लिए 14295 करोड़ रुपए की, जैसा कि उक्त समाचार में उल्लेख किया गया था । मई, 1992 के प्रथम सप्ताह में बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई ।

(ख) योजना आयोग, (न कि सार्वजनिक निवेश बोर्ड) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के परामर्श से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक परियोजनाओं के लिए योजना, निधियों का आवंटन, परियोजनाओं की आवश्यकताओं एवं निधियों की उपलब्धता के आधार पर करता है । ऊपर (क) में उल्लिखित तीन परियोजनाओं के लिए आवंटित अपर्याप्त नहीं है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

NRI Investment during the Eighth Plan period

3578. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the success of the Eighth Plan will depend a good deal on massive financial inputs including those of the NRIs;

(b) whether any estimate has been made of the mantum of NRI investments expected;

(c) whether Government are aware that the NRIs are beginning to grow restive due to slowing down of the new liberal policies;

(d) whether Government are aware that the MMPO ntroduced for milk has caused serious doubts in the mind of not only the NRIs, and MNCs as also the top Indian firms who are on the midway of planning/expansion of new projects both for exports and internal use; and

(e) whether Government will reconsider its stand and review MMPO in order to reassure the investors mentioned above?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE